मजदूरी को राजी नहीं पहाड़ के पढ़े-लिखे

ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) की सफलता के कारण भी ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में काफी वोट मिले. इसीलिए हम पेश कर रहे हैं नरेगा का लेखा-जोखा. इस सीरीज में हम इस योजना की जमीनी हालत बताने की कोशिश कर रहे हैं. आप पढ़ चुके हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का हाल. आज पढ़िए उत्तराखंड के बारे में.

जमीनी हालात-6

हिन्दुस्तान टीम देहरादून

नरेगा के सपने में उत्तराखंड में परवान नहीं चढ़ पाए। राज्य में योजना किसी तरह घिसट रही है। न तो 100 दिन का रोजगार पाने के सपने पूरे हुए हैं और न ही गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और पलायन रोकने में उल्लेखनीय काम हो सका है। योजना को लेकर कई नीतिगत मसले अब तक नहीं सुलझ पाए हैं। मसलन मजदूरी की दर सौ रुपये बाजार दर से कम है। इसलिए लोग योजना के तहत काम करने को राजी नहीं हैं। सौ दिन का रोजगार देकर पलायन रोकने की बात भी असरदार साबित नहीं हुई। पहाड़ में पलायन अमूमन पढ़े-लिखे युवा वर्ग की समस्या है। यह वर्ग मजदूरी करने को राजी नहीं है। पौड़ी जिले में योजना के तहत जल संरक्षण के लिए खाल, चाल, वनीकरण आदि कार्य कराए जा रहे हैं। यह काम जरूर सराहनीय हुआ है। यहां केवल 30 परिवारों और चंपावत जिले में 729 लोगों को ही सौ दिन का रोजगार मिल सका है। उत्तरकाशी जिले में 19 हजार 63 लोगों को सौ दिन का रोजगार मिला लेकिन पात्रों की संख्या के अनुरूप यह संख्या बहुत कम है। राज्य के अन्य जिलों का भी यही हाल है। राज्य के एक भी जिले में नरेगा की राशि पूरी तरह खर्च नहीं हो पाई है। योजना के संचालन के लिए पर्याप्त व अनुभवी स्टाफ न होने और ग्राम रोजगार सहायक के पदों पर नियुक्ति न किए जाने से कार्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि नरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और पलायन रोकने में मदद मिली है।

नैनीताल के डीडीओ टीएस बृजवाल का कहना है कि, नरेगा लागू होने के बाद मेहनत-मजदूरी करने वाले तबके के पलायन में 50

हिन्दुस्तान

उत्तराखंड में नरेगा की स्थिति

कुल जॉब कार्ड धारक	8.22 लाख
ऐसे जॉब कार्ड धारक जिनका बैंक में खाता है	7.22 लाख
बीते वर्ष रोजगार से लाभान्वित हुए परिवार	2.98 लाख
कुल राशि जो रोजगार पर खर्च हुई	135.79 लाख
कुल प्राप्त शिकायतें	283
निस्तारित की गई शिकायतें	250
लंबित शिकायतें	23
दैनिक मजदूरी	100 रुपए

कार्यों का स्वरूप : जल संवर्द्धन, भू-संरक्षण, वनीकरण, बाढ़ नियंत्रण, ऐसे कच्चे संपर्क मार्ग जो कि दो-तीन गांवों को जोड़ते हों और जिनकी पूरे वर्ष जरूरत पड़ती है।